भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2308
उत्तर देने की तारीख 03.08.2023

एमएसएमई पंजीकरण पोर्टल

2308. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और सरकार के एमएसएमई पंजीकरण पोर्टल 'उद्यम' प्लेटफार्म ने इस पर पंजीकृत एमएसएमई के आंकड़ों को जीईएम के साथ साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जीईएम का 'उद्यम' पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और जीईएम-पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग के माध्यम से ऑनलाइन बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या यह भागीदारी सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और एक्सपो में भाग लेने के साथ-साथ मेक इन इंडिया पहलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है ताकि सरकारी खरीदारों को अपने एमएसई-खरीद लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग मिल सके;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (घ): जी हां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.06.2023 को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई का सहमति आधारित डेटा साझा करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के अनुसार, जेम (जीईएम) में एकीकृत सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एमएसएमई के साथ अंतिम स्तर तक के संपर्क के लिए पक्ष समर्थन, जागरुकता, आउटरीच, गतिशीलता और क्षमता निर्माण का प्रस्ताव है।

(ड.) और (च) : एमओयू के अनुसार, जीईएम का कार्य सभी व्यापार मेलों प्रदर्शनियां, एक्सपो और क्षेत्र आधारित कॉन्क्लेव में सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए विक्रेता पंजीकरण और जीईएम पोर्टल पर ऑन-बोर्डिंग के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में अंतिम छोर पर स्थित उद्यम-सत्यापित एमएसई के लिए ऑनलाइन बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करना भी है।

(छ) : सरकार ने एसएसएमई क्षेत्र हेतु विपणन सहायता के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को अपनाना; 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होना; अंतराष्ट्रीय सहयोग योजना और खरीद एवं विपणन सहायता योजना आदि का कार्यान्वयन शामिल है।

*****